

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 16, बुधवार, शाके 1944-अप्रैल 6, 2022 Chaitra 16, Wednesday, Saka 1944- April 6, 2022	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 6, 2022

संख्या प.2(8)विधि/2/2022.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अप्रैल, 2022 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022

(2022 का अधिनियम संख्यांक 10)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अप्रैल, 2022 को प्राप्त हुई)

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 में नयी धारा 331 का अंतःस्थापन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की विद्यमान धारा 330 के पश्चात् और विद्यमान धारा 332 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"331. आयोग से परामर्श.- (1) धारा 332 और धारा 333 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में राज्य लोक सेवा आयोग से, जिसे इसमें इसके पश्चात् आयोग कहा गया है, संविधान के अधीन उसके अपने कृत्यों के अतिरिक्त-

(क) सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों से संबंधित सभी मामलों पर, और

(ख) सेवा के सदस्यों को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनिक मामलों पर, परामर्श किया जायेगा।

(2) आयोग का उप-धारा (1) के अधीन उसे निर्दिष्ट किसी भी मामले पर सलाह देने का कर्तव्य होगा।

(3) आयोग का यह भी कर्तव्य होगा कि वह सेवा में या किसी श्रेणी या उसके प्रवर्ग में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं, यदि आवश्यक हों, संचालित कराये।

(4) आयोग, संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) के अधीन प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस धारा के अधीन सेवा के संबंध में आयोग द्वारा किये गये कार्य के बारे में एक रिपोर्ट सम्मिलित और समाविष्ट करेगा तथा ऐसी रिपोर्ट पर उक्त अनुच्छेद के उक्त खण्ड में यथा उपबंधित कार्यवाही की जायेगी।

(5) उप-धारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार सेवा में के अत्यावश्यक आधार पर भरे जाने के लिए अपेक्षित पदों के लिए परीक्षाएं संचालित कराने हेतु किसी अन्य प्राधिकारी या एजेंसी की सेवाएं ले सकेगी।

स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजन के लिए, शब्द "सेवा" से धारा 332 और धारा 333 में यथा विनिर्दिष्ट सेवाएं अभिप्रेत हैं।

प्रवीर भटनागर,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, April 6, 2022

No. F. 2(8)Vidhi/2/2022.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Nagarpalika (Sanshodhan) Adhiniyam, 2022 (2022 Ka Adhiniyam Sankhyank 10):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ACT, 2022

(Act No. 10 of 2022)

(Received the assent of the Governor on the 5th day of April, 2022)

An

Act

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2022.

(2) It shall come into force at once.

2. Insertion of new section 331, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- After the existing section 330 and before the existing section 332 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), the following new section shall be inserted, namely:-

“331. Consultation with Commission.- (1) As respects the services specified in section 332 and section 333, the State Public Service Commission, hereinafter referred to as the Commission, shall in addition to its functions under the Constitution, be consulted-

(a) on all matters relating to appointments to the Service by direct recruitment, and

(b) on all disciplinary matters affecting the members of the Service.

(2) It shall be the duty of the Commission to advise on any matter referred to it under sub-section (1).

(3) It shall also be the duty of the Commission to conduct examinations, if necessary, for appointments to the Service or to any grade or category thereof.

(4) The Commission shall include and embody, in its report presented under clause (2) of Article 323 of the Constitution, a report as to the work done by the Commission in relation to Service under this section and such report shall be dealt with as provided in the said clause of the said Article.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), the State Government may engage other authority or agency to conduct examinations for the posts in the Service required to be filled on urgent basis.

Explanation: For the purpose of this section, the word “Service” means services as specified in section 332 and section 333.”.

प्रवीर भटनागर,

Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।